रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263444 CG-DL-E-28052025-263444

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2316]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2025/ज्येष्ठ 7, 1947

No. 2316]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2025/JYAISTHA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2025

का.आ. 2370(अ).— केन्द्रीय सरकार, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 3 के अधीन सुशासन के हित में, नागरिकों के जीवन की सहुलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर सुगमता को सक्षम करने के लिए अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन की अनुमित देती है;

और जबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उक्त नियमावली के नियम 4 के अधीन यथा अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसने दिनांक 6 मार्च, 2025 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 13(2)/2020-ईजी-II(खंड-II) के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कतिपय सेवाओं के संबंध में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग के प्रयोजनार्थ से आधार अधिप्रमाणन की अनुमित प्रदान की है।

3478 GI/2025 (1)

अब, अतएव, केंद्रीय सरकार सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 3 और 5 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3एच के अधीन जमा किए गए मुआवजे के भुगतान के प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन की अनुमति देती है:

बशर्ते कि जिस व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, उसे सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने पर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. NH-11011/90/2024-LA]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2025

S.O. 2370(E).— Whereas, the Central Government under rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 allows Aadhaar Authentication on a voluntary basis by requesting entities, in the interest of good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access to service for them:

And whereas, the Ministry of Road Transport and Highways submitted a proposal as required under rule 4 of the said rules, to the Central Government in the Ministry of Electronics and Information Technology, which *vide* O.M No 13(2)/2020-EG-II(Vol-II) dated the 6th March, 2025 had allowed Aadhaar authentication for the purpose of usage of digital platforms to ensure good governance in respect of certain services provided online to the citizens.

Now, therefore, in pursuance of rules 3 and 5 of the Aadhar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Central Government herby allows the Aadhar Authentication for the purposes of payment of compensation deposited under section 3H of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956):

Provided that the person who does not hold an Aadhar number shall be paid compensation on production of alternate and viable means of identification to the satisfaction of the competent authority.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. NH-11011/90/2024-LA] SHAIKH AMINKHAN, Director